सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल

School of Good Governance & Policy Analysis

तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन

(01 अप्रैल 2009 – 31 मार्च 2010)

Third Annual Report

(1st April 2009–31th March 2010)

सी–403, चतुर्थ तल, नर्मदा भवन, 59, अरेरा हिल्स,
भोपाल–462 011

अध्याय – एक

स्कूल की सामान्य जानकारी

1.1 स्कूल के उद्देश्य –

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11–8/2007/1/9 भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2007 द्वारा सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल की भोपाल में स्थापना की गई है। सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

- सुशासन के क्षेत्र में वैश्विक एवं स्थानीय (Global-Local) परिपेक्ष्य में थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। शासकीय नीतियों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव का आंकलन करना।
- सुशासन के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना, समस्याओं को चिन्हित कर उनका समाधान सुझाना, कार्य योजना बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करने में सहायता करना।
- उत्कृष्ट कार्य एवं विधियों तथा ई–प्रशासन के कार्यक्रमों का संकलन कर उनका विस्तारण करना।
- प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार एवं उनके स्वरूप में आवश्यक परिवर्तन संबंधी परामर्श देना।
- ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित करना, जिनमें परिवर्तन एवं सुधार से प्रशासनिक परिणामों तथा उपलब्धियों पर अधिकतम् सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो।
- प्रशासन को जन–केन्द्रित बनाने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा हितबद्ध समूहों के लिए मंच उपलब्ध कराना।
- स्थानीय निकाओं, राज्यों, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिये कार्यक्रमों की संरचना एवं संचालन एक्शन रिसर्च एवं प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों के लिये तकनीकी परामर्श एवं सेवायें उपलब्ध कराना।

1.2 स्कूल की अवधारणा **(vision)** –

“सुशासन जो सबको समान अवसर प्रदान करे एवं जिसका लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना हो।"

(“Equal opportunity to all through Good Governance geared to improve the quality of lives of our People”).

1.3 स्कूल के ध्येय **(mission)** –

“Knowledge Resource Hub और Repository के निर्माण एवं अन्य माध्यमों द्वारा सुशासन के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के विकास का प्रयास, सुनिश्चित करना, जिससे शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जनकल्याण केन्द्रित तथा जिम्मेदार और सुदृढ़ बनाया जा सके" ।

("Develop *Knowledge Resource Hub* and *Repository and other strategies*, to motivate and encourage strengthening of Good Governance which is more transparent, participative, accountable and focused on improving the quality of lives of our people").

1.4 स्कूल की कार्यप्रणाली –

संचालक सुशासन (Director Governance), संचालक नीति विश्लेषण (Director Policy Analysis) तथा संचालक प्रबन्धन (Director Knowledge Management), परियोजना / कार्यक्रम समन्वयक / अनुसंधान संयुक्त / शोधकर्त्ता (Project/ Programme Coordinators / Research Associates/ Research Fellows), तथा प्रशासनिक स्टाफ के सहयोग से स्कूल का कार्य संपादित होगा। परियोजनाओं से संबंधित विशिष्ट परामर्शदायी विशेषज्ञ / सलाहकार (Distinguished Specialists / Advisors), विशिष्ट फेलो / कन्सलटेंट (Distinguished Fellows/Consultants) संस्थागत / एक्सचेंज कार्यक्रम फेलों (Institutional Fellows, Exchange Programme Fellows) तथा कार्यक्षेत्र अनुभवी विशेषज्ञ (Experts with Field Experience) से भी सहयोग लिया जायेगा।

1.5 स्कूल के कार्य स्तंभ –

- शोध, नीति विश्लेशण एवं विकास
- सुशासन के लिए क्षमता के विकास को प्रोत्साहन
- प्रबंधन तकनीकियों का सुशासन के लिये उपयोग

1.6 स्कूल के कार्यक्षेत्र की दिशाएँ –

- शासन में नवाचार
- सेवाओं में सुधार और *grassroots* तक विस्तार
- शासन का विकेन्द्रीकरण
- अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास
- शासन में आम समाज की साझेदारी
- ई–शासन
- सुशासन के लिए *knowledge hub* और *repository* का निर्माण
- समान उद्देश्यों वाली अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग एवं समन्वय की स्थापना
- सुशासन को प्रोत्साहन

1.7 स्कूल के संकल्प –

- सुशासन संबंधी नीतियों के पालन में शासन को सहयोग प्रदान करने के लिए स्कूल संकल्पित है।
- स्कूल विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं विशेशज्ञों के साथ मिलकर सुशासन स्थापित करने को प्रोत्साहित करेगा।
- आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के प्रयासों में स्कूल सहयोगी होगा।

––00––

अध्याय – दो

वर्ष 2009–10 की मुख्य गतिविधियॉ

2.1 इन्टर्नशिप व्यवस्था –

शासन तंत्र से आई.आई.एम एवं आई.आई.टी. जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं के विषय विशेषज्ञों को जोडने हेतु स्कूल द्वारा वर्ष 2009 से इंटर्नशिप व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था अंतर्गत वर्ष 2009 में माह अप्रैल 2009 से मई 2009 के बीच आईआईएम इन्दौर के पॉच छात्र, आईआईटी कानपुर के 12 छात्र, आईआईएफएम भोपाल के 03 छात्र, इस प्रकार कुल 20 चयनित छात्रों द्वारा विभिन्न विभागों की नीतियों/ कार्यक्रमों का अध्ययन कर अपने सुझाव दिये गये हैं।

वर्ष 2010 में इन्टर्नशिप व्यवस्था अंतर्गत 200 से अधिक आवेदन देश की ख्याति प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त हुए है। वर्ष 2010 के लिए इन्टर्नशिप अंतर्गत कुल 20 छात्रों का चयन किया गया है जिनमें से 6 छात्र आईआईटी कानपुर से, 1 छात्र आईआईटी दिल्ली से, 03 छात्र आईआईएफएम भोपाल से, 05 छात्र एक्सआईएम भुवनेश्वर से, 01 छात्र आईआईटी मद्रास से, 01 छात्र वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय से, 01 छात्र इएमपीआई नई दिल्ली से एवं 02 छात्र आईआरएमए – आनन्द से है।

उपरोत इन्टर्नस पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग से संबंधित योजनाओं/नीतियों, जिनका चयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा, का अध्ययन करेंगें।

2.2 ''आइडियाज़ फॉर सीएम'' बेवसाईट –

आम जनता को सुशासन एवं विकास की वैचारिक प्रक्रिया से व्यापक रूप से जोड़ने एवं इनके अनुभव और ज्ञान के अपार भण्डार का लाभ प्रदेश के विकास की प्रक्रिया में लेने के लिए स्कूल द्वारा ''आइडियाज़ फॉर सीएम'' वेबसाईट का निर्माण किया गया है। इस वेबसाईट के माध्यम से विश्व के किसी भी हिस्से से सुशासन एवं विकास के संबंध में सुझाव प्रेषित किये जा सकते हैं। इस बेवसाईट को www.ideasforcm.in पर देखा जा सकता है।

मार्च–2010 तक इस वेबसाईट के माध्यम से लगभग 2875 आईडियाज़ प्राप्त हुए हैं। अभी तक 10 आईडियाज़ का क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया है।

प्राप्त आईडियाज के विश्लेषण एवं अनुश्रवण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन रखी गई है। नागरिकों द्वारा किसी आईडिया को प्रेषित करते ही उन्हें ई–मेल के माध्यम से आईडिया प्राप्त होने की सूचना दी जाती है। आईडिया की प्रारंभिक छानबीन के उपरांत यदि आईडिया अग्रिम विश्लेषण हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो उस आईडिया को पंजीकृत कर संबंधित विभाग को अभिमत हेतु ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है। साथ ही सुझावकर्ता को भी ई–मेल के माध्यम से उसके सुझाव के पंजीयन की सूचना देते हुए एक आई–डी एवं पासवर्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से सुझावकर्ता उसके आईडिया पर समय–समय पर की गई कार्यवाही की स्थित जान सकता है। यदि प्रारंभिक छानबीन के उपरांत आईडिया अग्रिम विश्लेषण हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उस स्थित में भी सुझावकर्ता को ई–मेल के माध्यम से सूचना दी जाती है। पंजीकृत आईडिया पर विभाग का अभिमत प्राप्त होने के उपरांत पुनः आईडिया का परिक्षण एक समिति द्वारा किया जाता है। तदोपरांत आईडिया के क्रियान्वयन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाता है। इस निर्णय के संबंध में भी सुझावकर्ता को ई–मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है।

2.3 Good Practices के संकलन का प्रकाशन –

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल के उद्देश्यों ने शासन में प्रचलित Good Practices के संकलन, विस्तार एवं प्रसारण की व्यवस्था निहित है। इस कार्य को व्यवस्थित एवं सतत् रूप से संचालित करने के लिये मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। स्कूल द्वारा सभी शासकीय विभागों से प्रस्ताव प्राप्त किये गये तथा उनकी संक्षेपिका समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा चुने गये प्रस्तावों से संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुतिकरण हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रकार समिति द्वारा 09 प्रस्ताव चुने गये। इन सभी प्रस्तावों को मुख्य सचिव महोदय से समक्ष विचारार्थ रखा गया। इस प्रकार मुख्य सचिव द्वारा 03 Good Practices का चयन किया गया। उपर्युक्त चयनित Good Practices एवं स्कूल द्वारा राष्ट्र

स्तर पर चयनित Good Practices का संकलन किया गया तथा इन्हें एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तिका को वृहद् रूप से प्रसारित किया गया।

2.4 मंथन–2009 का आयोजन –

राज्य शासन की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श हेतु राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 5–6 अक्टूबर एवं 14 अक्टूबर 2009 को प्रशासन अकादमी भोपाल में किया गया था। विचार विमर्श हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार 7 समूह का गठन किया गया था:–

1. सुशासन एवं संसाधन विकास समूह
2. अधोसंरचना समूह
3. कृषि को फायदे का धंधा बनाना
4. सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था
5. महिला सशक्तिकरण समूह
6. निवेश वृद्धि समूह
7. शिक्षा एवं स्वास्थ्य समूह

इस कार्यशाला में सभी माननीय मंत्रीगण, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव चयनित विभागों के विभागाध्यक्ष एवं समस्त कलेक्टर्स तथा 10 चयनित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पुलिस तथा वन विभाग के 10–10 अधिकारियों ने भाग लिया था। कार्यशाला के उपरान्त सभी समूहों द्वारा संबंधित विभागों को उनसे संबंधित अनुशंसाए प्रेषित की गई थी। संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न समूहों से उनके विभाग से संबंधित प्राप्त अनुशंसाओं का परीक्षण किया जाकर उनके क्रियान्वयन की योजना बनाकर प्रस्तुतीकरण माननीय मुख्यमंत्रीजी/अन्य मंत्रीगणों के समक्ष किया गया है। प्रस्तुतीकरण के समय अनुमोदित अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जा रही है।

इस राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन हेतु सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल द्वारा नोडल एजेन्सी की भूमिका का निर्वहन किया गया है। स्कूल द्वारा ''मंथन–2009'' अंतर्गत बनाए गए सात समूहों – निवेश वृद्धि, अधोसंरचना, कृषि को फायदे का धंधा बनाना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था तथा

सुशासन एवं संसाधन कार्य समूह की अनुशंसाओं के संकलन का प्रकाशन भी किया गया है।

2.5 शासकीय नीति/कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव के आंकलन –

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल द्वारा शासकीय नीति/कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव के आंकलन संबंधी उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यकारी निकाय के अनुमोदन उपरान्त प्रारम्भिक तौर पर आम जनता से जुड़ी हुई कुछ योजनाओं जैसे–जननी सुरक्षा योजना, बलराम तालाब योजना, माइक्रोएरिगेशन योजना, कपिलधारा योजना का अध्ययन कार्य शुरू किया गया है।

2.6 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की सम्पूर्ण परीक्षा प्रणाली का अध्ययन –

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा विज्ञापन से लेकर परिणाम घोषित करने तक की अपनी सम्पूर्ण परीक्षा प्रणाली का अध्ययन कर प्रणालीगत सुधार हेतु सुझाव देने का कार्य सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल को सौंपा गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं सुरक्षा को बढ़ाना है। स्कूल द्वारा यह अध्ययन 3 माह में पूर्ण किया जाकर अपना प्रतिवेदन व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को सौंपा गया है।

2.7 ''Assesment of the improvement in quality of life of Madhya Pradesh Rural Livelihood Project (MPRLP) beneficiaries'' –

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ''मध्यप्रदेश ग्रामीण आजिविका परियोजना'' के प्रभाव का आंकलन करने हेतु एक अध्ययन ''Assesment of the improvement in quality of life of Madhya Pradesh Rural Livelihood Project (MPRLP) beneficiaries'' सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल को सौंपा गया है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य आजिविका परियोजना अंतर्गत किए गए हस्तक्षेप से ग्रामीणों के जीवन में आए बदलावों का विस्तृत अध्ययन कर परियोजना के प्रभावों का आंकलन करना है, जिससे कि इस योजना के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाया जा सके।

इस योजना के प्रभाव के आंकलन हेतु परियेाजना क्षेत्र के समस्त 09 जिलों के 54 गावों में लगभग 1500 लाभार्थियों का अध्ययन किया गया है जिसके अंतर्गत संख्यात्मक एवं

गुणात्मक आंकडों का संग्रहण किया गया है। इन आंकडों का विश्लेषण कार्य प्रगति पर है एवं शीघ्र ही स्कूल द्वारा अपना प्रतिवेदन ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा जाएगा।

2.8 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग एवं समन्वय के प्रयास –

2.8.1 शेफील्ड हलाम विश्वविद्यालय यू.के. – वर्ष 2009–10 में स्कूल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग एवं समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। माह दिसम्बर 2009 में शेफील्ड हलाम विश्वविद्यालय यू.के. के प्रोफेसर एण्डी डीयरडेन, द्वारा भ्रमण किया गया। इस भ्रमण का उद्‌देश्य शेफील्ड हलाम विश्वविद्यालय द्वारा भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के क्षेत्र में किए गए ''खेती'' तकनीक के प्रसार की खोज को तलाशना था, जिससे इस तकनीक के माध्यम से मध्यप्रदेश के गरीब लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। उक्त विश्वविद्यालय के साथ अन्य क्षेत्रों विशेषकर संयुक्त शोध, विकास हस्तक्षेपों में तकनीकी प्रयोग, कार्यशाला/सेमीनार/कान्फ्रेंस का आयोजन आदि पर संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए सहमति बनी है।

2.8.2 नेशनल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर – नेशनल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर के साथ स्कूल ने सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसके तहत सुश्री अनन्या समजदार को स्कूल में इंस्टीट्‌यूशनल फैलो के रूप में नियुक्त किया गया तथा सुश्री समजदार को उनके पीएचडी शोध जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन है, में विधिवत अकादमिक एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया गया। स्कूल के कोर स्टॉफ एवं नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर के कोर स्टॉफ के मध्य भविष्य में संयुक्त कार्य करने पर चर्चा की गई।

2.8.3 हल यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल – डॉ. आशीष द्विवेदी, लेक्चरर इन इन्फार्मेशन साइंस, हल यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ हल द्वारा 12–13 जनवरी 2010 को स्कूल का भ्रमण किया गया। डॉ. द्विवेदी से स्कूल के कोर स्टाफ की चर्चा के दौरान आम जनता से जुडे हुए कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन करने एवं ''नालेज एण्ड इन्फारमेशन रिपॉसिटरी'' के निर्माण में हल यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु सहमति बनी है।

2.8.4 वाटशन बिजनेस स्कूल यू.के. – वाटशन बिजनेस स्कूल के डायरेक्टर डॉ. ए.के. जैन द्वारा माह दिसम्बर 2009 में स्कूल का भ्रमण किया गया। डॉ. जैन द्वारा वाटशन बिजनेस स्कूल तथा सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल के बीच भावी सहयोग के ऊपर चर्चा की गई।

2.8.5 नेपाल सरकार के विशिष्ट मंडल का भ्रमण – श्री कृष्णा ग्यावली, सचिव, स्थानीय विकास मंत्रालय, नेपाल सरकार की अगुवाई में नेपाल के 20 वरिष्ठ अधिकारियों के दल द्वारा स्कूल का भ्रमण किया गया एवं स्कूल के कोर स्टॉफ के साथ चर्चा की गई। चर्चा में अन्य विषयों के अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 अंतर्गत मध्यप्रदेश में किए गए प्रयासों पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

––00––

अध्याय – तीन

सेमीनार / कार्यशालाऐं

3.1 **Website Quality, Accessibility and Security** विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला –

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल द्वारा Website Quality, Accessibility and Security विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 02 अप्रैल 2009 को होटल जहॉनुमा पैलेस में भारत सरकार के सूचना प्रोद्योगिकी विभाग अन्तर्गत Stardardization Testing and Quality Certification (STQC) तथा सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इसमें मध्यप्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं ICT से जुडे अधिकारियों की सहभागिता रही। इस कार्यशाला को तकनीकी सहयोग STQC, NIC एवं gtz द्वारा प्रदाय किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री राकेश साहनी मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया गया। कार्यशाला में श्री शेखर दत्त उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत सरकार, श्री डी.एस. माथुर पूर्व सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, श्री गुलशन राय, महानिदेशक STQC, श्री अनुराग जैन सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी एवं श्री हैन्स कारकोस्की, ई–गवर्नेंस सलाहकार, gtz (जर्मन सरकार की संस्था) की विशेष उपस्थिति रहीं।

3.2 **Disseminating information on Best Practices in Public Service Delivery** विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला –

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल द्वारा राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार तथा राज्य शासन के सहयोग से Disseminating information on Best Practices in Public Service Delivery विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 05 जून 2009 को किया गया है। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर पर एवं मध्यप्रदेश में आम नागरिकों को सेवायें प्रदाय करने के संबंध में किये गये अभिनव प्रयोगों पर चर्चा की गई।

3.3 ''जनजातीय स्वास्थ्यः स्थिति, चुनौतियॉ एवं संभावनाएं'' विषय पर कार्यशाला –

जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था मध्यप्रदेश शासन द्वारा ''जनजातीय स्वास्थ्यः स्थिति, चुनौतियॉ एवं संभावनाएं'' विषय पर दिनांक 17 एवं 18 दिसम्बर 2009 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भोपाल में किया गया है। सुशासन एवं नीति विश्लेषण द्वारा इस राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन में तकनीकी सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया गया है।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में माननीय श्री कुंवर विजय शाह मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे एवं उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता श्री आर.पी. कपूर पूर्व मुख्य सचिव मध्यप्रदेश द्वारा की गई। प्रो. सच्चिदानंद पूर्व कुलपति रांची विश्वविद्यालय द्वारा उद्घाटन संबोधन दिया गया । समापन सत्र की अध्यक्षता श्री के.एस. शर्मा पूर्व मुख्य सचिव मध्यप्रदेश द्वारा की गई एवं डॉ. वर्जिनियस हाहा प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा समापन उद्बोधन दिया गया। दो दिवसीय कार्यशाला कें सात तकनीकी सत्रों में 28 प्रस्तुतिकरण मध्यप्रदेश एवं मध्यप्रदेश के बाहर के विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए।

----00----

अध्याय – चार

वित्तीय प्रतिवेदन

वर्ष 2009–10 में स्कूल के लिए रूपये 1026 लाख का बजट प्रावधान निम्नानुसार प्रस्तावित था –

मान संख्या – 01

मुख्य शीर्ष – 2052 – सचिवालयीन सामान्य सेवायें

राज्य आयोग (सामान्य) – 101

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल की स्थापना (5163)

मद		राशि (हजार रूपयों में)
001–अद्योसंरचना अनुदान	–	9,00,00
002–संधारण अनुरान	–	1,26,00
योग		**10,26,00**

उपरोक्त प्रावधानित राशि में से वित्त विभाग की अनुमति से रूपये 806 लाख का आहरण वर्ष 2009–10 में किया गया है।

––00––

अध्याय – पॉच

नवीन नियुक्तियॉ

5.1 डॉ. सैय्यद मोहम्मद हैदर रिजवी, ने अक्टूबर 2009 में स्कूल में संचालक (नीति विश्लेषण) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। डॉ. रिजवी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त की है एवं स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उन्होनें शेफील्ड हालम विश्वविद्यालय, यू.के., अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन, आगा खॉ एज्यूकेशन सर्विस, वीवी गिरी नेशनल लेबर इन्स्टीट्यूट, प्रयास जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं में कार्य किया है।

5.2 श्री कुलदीप सिंह चौहान ने फरवरी 2010 में स्कूल में प्रबंधक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। श्री चौहान राज्य वित्त सेवा के अधिकारी है एवं सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल से लेखाधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए है।

5.3 श्री जी.एस. शर्मा ने फरवरी 2010 में स्कूल में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। श्री शर्मा, सितम्बर 2009 में आर्मी से सूबेदार मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए है।

5.4 डॉ. अमित कुमार श्रीवास्तव ने दिसम्बर 2009 में स्कूल में कार्यक्रम समन्वयक (नीति विश्लेषण) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। डॉ. श्रीवास्तव ने लखनऊ विश्वविद्यालय से गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त की है एवं स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व वे ईग्नू में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में जबलपुर रीजन में पदस्थ थे।

5.5 श्रीमती ऋचा मिश्रा ने जनवरी 2010 में स्कूल में कार्यक्रम समन्वयक (सुशासन) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। श्रीमती मिश्रा ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से एम.ए. (समाजशास्त्र) एवं विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की है एवं स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व वे तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत मण्डला में जिला कार्यक्रम प्रबंधक (तेजस्विनी परियोजना) के रूप में कार्यरत रही है।

5.6 श्री गौरव खरे ने नवंबर 2009 में स्कूल में परियोजना अधिकारी (ज्ञान प्रबंधन) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। श्री खरे ने जेवियर इन्स्टीट्यूट ऑफ

डेवलपमेंट एक्शन एण्ड स्टडीज, जबलपुर से एम.बी.ए. की उपाधि प्राप्त की है एवं स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व वे बैफ (BAIF), भोपाल में वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्यरत रहें है।

5.7 श्री गौरव अग्रवाल ने नवंबर 2009 में स्कूल में परियोजना अधिकारी (नीति विश्लेषण) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। श्री अग्रवाल ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर से एम.बी.ए. की उपाधि प्राप्त की है एवं स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर में बिजनेस मैनेजर के रूप में कार्यरत रहें है।

5.8 श्री अमिताभ श्रीवास्तव ने दिसंबर 2009 में स्कूल में प्रबंधक (KAIR) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। श्री श्रीवास्तव ने डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर से एम.लिब. की उपाधि प्राप्त की है एवं स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व वे आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में सहायक लायब्रेरीयन के रूप में कार्यरत रहें है।

——00——

अध्याय – छः

स्कूल/कोर स्टाफ को प्राप्त सम्मान/अवार्ड

6.1 आईडियाज फार सीएम वेबसाईट को पब्लिक पार्टिसिपेशन श्रेणी में ''वेबरत्न अवार्ड–2009'' (सिल्वर आईकन) की प्राप्ति –

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2009 से विभिन्न श्रेणियों हेतु ''वेबरत्न अवार्ड'' की स्थापना की गई है।

आम जनता को सुशासन एवं विकास की वैचारिक प्रक्रिया से व्यापक रूप से जोड़ने एवं इनके अनुभव और ज्ञान के अपार भण्डार का लाभ प्रदेश के विकास की प्रक्रिया में लेने के लिए स्कूल के प्रयास ''आइडियाज़ फॉर सीएम'' वेबसाईट को पब्लिक पार्टिसिपेशन श्रेणी में ''वेबरत्न अवार्ड–2009'' (सिल्वर आईकन) के लिए चयन किया गया है। यह अवार्ड सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2010 में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। स्कूल की ओर से इस वेबसाईट से संबंधित कार्य का समन्वय श्री अखिलेश अर्गल, संचालक (सुशासन) द्वारा किया जाता है।

6.2 डॉ. एस.एम. हैदर रिजवी, संचालक (नीति विश्लेषण) सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल को ''मंथन साउथ एशिया अवार्ड–2009'' की प्राप्ति–

डॉ. एस.एम. हैदर रिजवी, संचालक (नीति विश्लेषण) एवं डॉ. एण्डी डीयरडेन, शेफील्ड हालम विश्वविद्यालय को सम्मिलित रूप से ''मंथन साउथ एशिया अवार्ड–2009'' से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड इनके KHETI (Knowledge Help Extention Technology Initiative) के लिए दिया गया है।

----00----

अध्याय – सात

कोर स्टॉफ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विशिष्ट कार्यक्रमों में सहयोग एवं प्रकाशन

7.1 डॉ. एच.पी. दीक्षित, महानिदेशक, सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल द्वारा आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में ''कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम'' अंतर्गत अकादमी में भ्रमण पर आए नाईजिरिया के वरिष्ठ अधिकारियों के शिष्ट मंडल को सुशासन विषय पर संबोधित किया गया।

7.2 Dr. H.P. Dikshit delivered the Inaugural Address at an International Conference on Optimization at Banaras Hindu University on December 16, 2009 and Presidential Address at another International Conference of International Society for Applications of Physical Sciences on December 19, 2009 at the University of Allahabad.

7.3 श्री अखिलेश अर्गल, संचालक (सुशासन) को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के कलेक्टर्स, एस.पी. एवं डी.एफ.ओ. स्तर के अधिकारियों के ''सूचना का अधिकार–चुनौतियॉ एवं संभावनाऐं'' विषय पर आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम (25–27 फरवरी 2010) के पैनल डिस्कशन में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया जिसमें श्री अर्गल द्वारा प्रतिभागियों से चर्चा की गई।

श्री अर्गल आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में ''सूचना के अधिकार विषय'' पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी रिसोर्स पर्सन के रूप में नियमित रूप से अपनी सेवाऐं दी हैं।

7.4 प्रकाशन –

7.4.1 Publication of Dr. Zakir Hussain Award Lecture, by Dr. H.P.Dikshit, entitled “Geometric Modelling and Shape Preserving Properties of Wachspress Functions”, in Proceedings of an International Conference on Modelling and Engineering and Technological Problems, Editors: M. Brokate et al. American Institute of Physics Conference Proceedings, Vol. 1146, Melville, New York, 2009, pp.18-38.

7.4.2 Dr. H.P.Dikshit continued to be a Reviewer for research review journals *Mathematical Reviews* and *Zentralblatt fur Mathematik* published by the American Mathemeatical Society, USA and Springer-Verlag, Germany.

7.4.3 A. Dearden and H. Rizvi. Roles, Boundaries and Communications in Agile ICT for Development. Appeared in International Conference Proceedings on HCI 2010/IDID 2010 organized by IIT, Mumbai on 22-24 March 2010

7.4.4 A. Dearden & H Rizvi. A Deeply Embedded SocioTechnical Strategy for Designing ICT for Development. International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development. October – December 2009, Vol. 1, No. 4. IGI Publishing, USA

अध्याय – आठ

परिशिष्ट

8.1 स्कूल की गवर्निंग बॉडी –

स्कूल की गवर्निंग बॉडी निम्नानुसार है

1.	माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्रीजी, वित	सदस्य
3.	माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	सदस्य
4.	माननीय मंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास	सदस्य
5.	माननीय मंत्रीजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सदस्य
6.	माननीय मंत्रीजी, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण	सदस्य
7.	माननीय मंत्रीजी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय	सदस्य
8.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
9.	महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी.प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
12	संचालक, भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर	सदस्य
13	राज्य शासन द्वारा नामांकित प्रशासन एवं प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पांच सदस्य	सदस्य
14	महानिदेशक, सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल	सदस्य सचिव

सरल क्रमांक 13 के प्रावधान के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11–8/2007/1/9 दिनांक 22 अप्रैल 2008 द्वारा निम्नांकित पॉच सदस्यों को आदेश दिनांक से अशासकीय सदस्य के रूप में गवर्निंग बॉडी हेतु नामांकित किया है–

1. डॉ. सोमपाल शास्त्री, उपाध्यक्ष योजना आयोग, मध्यप्रदेश
2. डॉ. बकुल ढोलकीया, पूर्व निदेशक, आईआईएम अहमदाबाद
3. डॉ. एम राय, महानिदेशक, इण्डियन काउन्सिल फॉर एग्रिकल्चर रिसर्च, भारत सरकार
4. डॉ. बी.एस. बासवान, निदेशक, आईआईपीए, नई दिल्ली

5. डॉ. राजीव करदिनकर, उपाध्यक्ष कैन्स साफ्टवेयर बेंगलोर

नामांकित सदस्यों का कार्यकाल प्रारंभ में दो वर्ष का रहेगा जिसे राज्य शासन द्वारा बढाया भी जा सकता है।

8.2 स्कूल की एक्जिक्यूटिव बॉडी –

स्कूल की एक्जिक्यूटिव बॉडी निम्नानुसार है

क्र.	सदस्य नाम / पद	धारित पद
1.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव / सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	सदस्य
8.	शासन द्वारा नामांकित अधिकतम पांच अशासकीय सदस्य	सदस्य
9	महानिदेशक, सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल	सदस्य सचिव

सरल क्रमांक 8 के प्रावधान के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11–8 / 2007 / 1 / 9 दिनांक 22 अप्रैल 2008 द्वारा निम्नांकित पॉच सदस्यों को आदेश दिनांक से अशासकीय सदस्य के रूप में एक्जीक्यूटिव बॉडी हेतु नामांकित किया है–

1. डॉ. डी.के. बन्धोपाध्याय, निदेशक, आईआईएफएम भोपाल
2. डॉ. वेद प्रकाश, वाइस चान्सलर, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एज्यूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली
3. प्रो. एस.सी. गर्ग, पूर्व प्रो–वाइस चान्सलर, इग्नू
4. डॉ. डी.एम. पेस्टोनजी, पूर्व प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद
5. प्रो. कर्मेषु, प्रोफेसर डिपार्टमेन्ट ऑफ सिस्टम साइन्स, जेएनयू, नई दिल्ली

नामांकित सदस्यों का कार्यकाल प्रारंभ में दो वर्ष का रहेगा जिसे राज्य शासन द्वारा बढाया भी जा सकता है।

––00––